उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए धनराशि का उपयोग ।

1729. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आबंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा आबंटित की गई निधियां और उत्तर प्रदेश में विगत तीन वर्षों के दौरान ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए सदुपयोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्नवत है :—

वर्ष	आबंटन	समुपयोजन
1989–90	139.35	87.94
1990–91	73.00	46.25
1991–92	68.32	86.50

ऊर्जा स्रोत एवं ऊर्जा खपत ।

1729. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में ऊर्जा की कुल खपत कितनी है और ऊर्जा उत्पादन के कौन-कौन से स्रोत हैं और प्रत्येक स्रोत से कितनी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है ; और

(ख) देश में विद्युत की कुल मांग कितनी है और इस मांग की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) अप्रैल, 1992—जनवरी, 1993 तक की अवधि के दौरान देश में ऊर्जा उत्पादन का श्रेणीवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

श्रेणी	ऊर्जा उत्पादन (मि० यू०)
ताप विद्युत	183871
न्यूक्लीय	5548
जल विद्युत	59579
जोड़	248798

(ख) अप्रैल, 1992—जनवरी, 1993 की अवधि के दौरान, देश में ऊर्जा की आवश्यकता 252810 मि० यू० थी जबकि इसकी उपलब्धता 231371 मि० यू० थी जोकि 8.5 प्रतिशत कमी का द्योतक है । उक्त कमी को पूरा करने के उद्देश्य से देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं :—नई विद्युत उत्पादन क्षमता शीघ्र चालू करना, कम निर्माण अवधि वाली विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, मांग, प्रबंधन एवं ऊर्जा संरक्षण उपायों को कार्यान्वित करना और अधिक ऊर्जा वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा की सप्लाई करना ।

Curtailment of subsidies to State Power Boards

1730. SHRI B. K. HARIPRASAD : Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) whether Government are considering to curtail the subsidies to State Power Boards which are in the red;

(b) if so, whether Government would insist on proper management of generation and distribution machinery; and